

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 645

24/07/2026 को उत्तरार्थ

विषय: पंजाब में पीएम-किसान का कार्यान्वयन

645. श्री तरुण चुघ:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पंजाब में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत शामिल लाभार्थियों की संख्या और पिछले चार वर्षों के दौरान इस योजना के तहत संवितरित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या पंजाब में किसानों द्वारा कृषि आदानों और संबद्ध कृषि गतिविधियों के लिए पीएम-किसान सहायता के उपयोग का कोई आकलन किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या पात्र किसानों को लाभ का निर्बाध हस्तांतरण सुनिश्चित करने और पंजाब में लाभार्थियों की पहचान में सुधार के लिए कोई उपाय किए गए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पीएम-किसान के तहत, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत के बाद से 23 किस्तों के माध्यम से 4.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है। पिछले 4 वर्षों में पंजाब राज्य में जारी किए गए पीएम-किसान लाभों का वर्षवार एवं किस्तवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): पंजाब सहित देशभर में किसानों द्वारा पीएम-किसान सहायता राशि का कृषि इनपुट और कृषि से संबद्ध गतिविधियों में उपयोग के संबंध में नीति आयोग द्वारा एक अध्ययन किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि यह योजना कृषि भूमि धारक किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने मूल उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि 92 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी किसानों ने वित्तीय सहायता का उपयोग बीज, उर्वरक तथा कीटनाशकों जैसे आवश्यक कृषि इनपुट के लिए किया, जो विशेष रूप से बढ़ती इनपुट लागत तथा मौसम संबंधी अनिश्चितताओं के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

(ग): पीएम-किसान योजना के तहत, पंजाब सहित देशभर के किसान पीएम-किसान पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने और लाभों के निर्बाध अंतरण के लिए, लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी और लाभार्थी के बैंक खाते के साथ आधार लिंकेज योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्तें हैं।

किसानों के पंजीकरण में सहायता प्रदान करने, पीएम-किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी की स्थिति का सत्यापन करने, भूमि विवरण अद्यतन करने, फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी पूर्ण कराने तथा बैंक खातों को आधार से लिंक कराने के लिए ग्राम नोडल अधिकारियों (Village Nodal Officers-VNOs) की नियुक्ति की गई है। इससे लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होती है तथा लाभ का निर्बाध अंतरण सुदृढ़ होता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रह जाए, भारत सरकार पंजाब सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय में संतृप्ति अभियान (Saturation Drives) चलाती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा (VBSY) के अंतर्गत 15 नवम्बर, 2023 से एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी संतृप्ति अभियान (Saturation Drive) चलाया गया, जिसके दौरान पीएम-किसान योजना में 1.0 करोड़ से अधिक किसानों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024 में सरकार की 100-दिनों की पहल के अंतर्गत 25 लाख से अधिक पात्र किसानों को पीएम-किसान योजना में जोड़ा गया।

साथ ही, लंबित स्व-पंजीकरण मामलों के निपटान के लिए सितंबर 2024 में एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 30 लाख से अधिक नए किसान योजना में जुड़े। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से 1 जून, 2026 से पीएम-किसान के तहत "खेत बचाओ अभियान" के साथ एक राष्ट्रव्यापी संतृप्ति अभियान (Saturation Drive) भी संचालित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत 17 लाख से अधिक नए किसानों को जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश भी समय-समय पर संतृप्ति अभियान चलाकर पात्र किसानों की पहचान करते हैं तथा उन्हें योजना के अंतर्गत नामांकित कराने में सहायता प्रदान करते हैं।

पिछले 4 वर्षों में पंजाब में पीएम-किसान के अंतर्गत जारी किए गए लाभों का वर्ष-वार, किस्त-वार

विवरण

	किस्त/भुगतान अवधि	लाभान्वित लाभार्थी	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये)
वित्तीय वर्ष 2022-23	11वीं किस्त (अप्रैल'22 - जुलाई'22)	16,97,641	340.99
	12वीं किस्त (अगस्त'22 - नवंबर'22)	2,07,569	41.87
	13वीं किस्त (दिसंबर'22 - मार्च'23)	8,61,065	308.71
वित्तीय वर्ष 2023-24	14वीं किस्त (अप्रैल'23 - जुलाई'23)	8,56,789	182.44
	15वीं किस्त (अगस्त'23 - नवंबर'23)	4,97,230	152.67
	16वीं किस्त (दिसंबर'23 - मार्च'24)	7,17,325	247.64
वित्तीय वर्ष 2024-25	17वीं किस्त (अप्रैल'24 - जुलाई'24)	8,40,275	290.56
	18वीं किस्त (अगस्त'24 - नवंबर'24)	9,26,314	272.86
	19वीं किस्त (दिसंबर'24 - मार्च'25)	10,58,889	373.15
वित्तीय वर्ष 2025-26	20वीं किस्त (अप्रैल'25 - जुलाई'25)	11,34,597	387.79
	21वीं किस्त (अगस्त'25 - नवंबर'25)	11,20,877	224.43
	22 वीं किस्त (दिसंबर'25 - मार्च'26)	11,42,925	228.60
वित्तीय वर्ष 2026-27 (16.07.2026 तक)	23वीं किस्त (अप्रैल'26 - जुलाई'26)	11,36,206	227.2412
